RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

INDORE 24 FEBRUARY TO 02 MARCH 2021 प्रति बुधवार वर्ष 06 अंक 27 पृष्ठ 8 कीमत 5 रु.

Inside News

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर बोले धर्मेंद्र प्रधान- GST के तहत लाने का प्रयास जारी Page 2

शेराटन ग्रैंड पैलेस को मिला 'लक्ज़रीयस एंड ग्रैंड फाइव स्टार प्रॉपर्टी' का खिताब Page 3

झंडु च्यवनप्राश का प्राकृतिक गुड़ के साथ एक नया वैरिएंट Page 7

editoria!

नियंत्रित हों कीमतें

देश के अनेक हिस्सों में पेट्रोल का खुदरा दाम प्रति लीटर सौ रुपये के आसपास या इससे अधिक है. ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में पूरे देश में पेट्रोल की दर सौ रुपये प्रति लीटर के पार होगी. इसी तरह डीजल तथा रसोई गैस के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं. कई महीनों से हमारी अर्थव्यवस्था महामारी और मुद्रास्फीति से त्रस्त है. अब जब धीरे-धीरे आर्थिक मोर्चे पर सकारात्मक रुझान दिखने लगे हैं, तो पेट्रोल और डीजल का महंगा होना हमें मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि मुद्रास्फीति को काबू में करना आसान नहीं होगा. तेल की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव का असर होता है, जिस पर सरकार या कंपनियों का नियंत्रण नहीं है. इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के कराधान से भी दाम में बढ़ोतरी होती है. पेट्रोल की कीमत में केंद्र व राज्य सरकारों के करों का हिस्सा लगभग 61 प्रतिशत तथा डीजल में 56 फीसदी से ज्यादा है. ऐसे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह सुझाव व्यावहारिक प्रतीत होता है कि केंद्र और राज्य सरकारें आपसी सहमति से अपने-अपने करों में कुछ कटौती करें या छूट दें ताकि ग्राहकों को कुछ राहत मिल सके. सीतारमण ने इस मसले को धर्मसंकट और चिंताजनक कहा है. सरकारों को सबसे अधिक, एक-तिहाई से अधिक, अप्रत्यक्ष कर पेट्रोलियम उत्पादों से ही हासिल होता है. इस कर की वसूली भी आसान होती है तथा इसमें चोरी या छुपाने की गुंजाइश भी बहुत ही कम होती है. इसका एक दूसरा पहलू यह है कि हमारे कुल निर्यात में पेट्रोलियम पदार्थों का हिस्सा भी एक-तिहाई के आसपास है. हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मुख्य रूप से आयात पर निर्भर हैं. यद्यपि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश हो रही है, पर पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कम करने में अभी बहुत समय लगेगा. ऐसी स्थिति में सरकारी करों के बारे में एक ठोस समझ बनाने की कोशिश की जानी चाहिए. इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट हो, तो उसका फायदा खुदरा ग्राहकों को भी मिले. इससे कीमतों के बढ़ने पर ग्राहकों को शिकायत नहीं होगी. यह मांग भी उठती रही है कि पेट्रोल, डीजल आदि उत्पादों को भी वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) के तहत लाया जाए. वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि जीएसटी व्यवस्था से शायद कोई समाधान निकल सकता है, लेकिन इसके लिए भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहमति बनानी होगी. सीतारमण ने भी रेखांकित किया है कि किसी भी सरकार के लिए राजस्व को छोड़ना आसान नहीं है. केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना महामारी से बचाव और आर्थिकी में सुधार के लिए अनेक प्रयास किये हैं. उसी कड़ी में उन्हें तेल की कीमतों में राहत देने के लिए भी पहल करनी चाहिए, ताकि महंगाई से अर्थव्यवस्था को नुकसान न हो.

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अभिन्न अंग बन रहे हैं किसान

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केदो साल पूरे होने पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इससे करोड़ों किसानों के जीवन में बदलाव आया है और वे 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के अभिन्न अंग बन रहे हैं। मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, "पीएम किसान निधि की लॉन्चिंग को आज दो साल पूरे हो रहे हैं। अन्नदाताओं के कल्याण को समर्पित इस योजना से करोड़ों किसान भाई-बहनों के जीवन में जो बदलाव आए हैं, उससे हमें उनके लिए और अधिक काम करने की प्रेरणा मिली है।"

उन्होंने कहा, "अन्नदाताओं के जीवन को आसान बनाने और उनकी आय दोगुनी करने का जो संकल्प देश ने लिया है, उसमें पीएम किसान निधि की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हमारे किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान के भी अभिन्न अंग बन रहे हैं। इस योजना की शुरुआत 2019 में आज ही के दिन हुई थी। इसके तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6000 रुपये जमा करती है। सरकार यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के खाते में डालती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का पेट भरने वाले मेहनतकश किसानों के जीवन में सम्मान और समृद्धि सुनिश्चित करने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई थी।

उन्होंने कहा, "हमारे किसानों का तप और जुनून प्रेरित करने वाला है।" मोदी ने कहा कि पिछले सात सालों में केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें सिंचाई के लिए बेहतर प्रावधान से प्रौद्योगिक का इस्तेमाल, अधिक ऋण और बाजार उपलब्ध कराने से लेकर उचित फसल बीमा और मिट्टी की सेहत संबंधी जांच पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में ऐतिहासिक वृद्धि करने का सम्मान मिला। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हम हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि "नमो एप" के माध्यम से किसानों के हित में उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी हासिल की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की सातवीं किस्त जारी की थी। किसानों और कृषि क्षेत्र के संबंध में प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर लगभग तीन महीने से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच अब तक 11 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है।

आधी हो सकती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें, सरकार कर रही है इस विकल्प पर विचार

नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) की कीमतें आसमान छू रही हैं। यदि केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी, GST) के दायरे में ले आए तो आम आदमी को राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसके संकेत भी दिए हैं। जीएसटी की उच्च दर पर भी पेट्रोल-डीजल को रखा जाए तो मौजूदा कीमतें घटकर आधी रह सकती हैं।

वर्तमान में, पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क और राज्य वैट वसूलते हैं। इन दोनों की दरें इतनी ज्यादा है कि 35 रुपए का पेट्रोल विभिन्न राज्यों में 90 से 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच रहा है। 23 फरवरी को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90.93 रुपए प्रति लीटर और डीजल 81.32 रुपए प्रति लीटर पर थी। इस पर केंद्र ने क्रमशः 32.98 रुपए लीटर और 31.83 रुपए लीटर का उत्पाद शुल्क लगाया है। यह तब है जबकि देश में जीएसटी लागू है। जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 को पेश किया गया था। तब राज्यों की उच्च निर्भरता के कारण पेट्रोल और डीजल को इससे बाहर रखा गया था। अब सीतारमण ने ईंधन की कीमतें नीचे लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त सहयोग का आह्वान किया।

जीएसटी में ईंधन को शामिल करने का यह असर होगा

अगर पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत शामिल किया जाता है, तो देश भर में ईंधन की एक समान कीमत होगी। यही नहीं, यदि जीएसटी परिषद ने कम स्लैब का विकल्प चुना, तो कीमतों में कमी आ सकती है। वर्तमान में, भारत में चार प्राथमिक जीएसटी दर हैं - 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत। जबकि अभी केंद्र व राज्य सरकारें उत्पाद शुल्क व वैट के नाम पर 100 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स वसूल रही हैं।

कमजोर मांग से कच्चातेल वायदा कीमतों में गिरावट

नयी दिल्ली। एजेंसी

कमजोर हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया जिससे वायदा बाजार में कच्चा तेल की कीमत बुधवार को 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,469 रुपये प्रति बैरल रह गयी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी महीने में डिलिवरी वाले कच्चा तेल अनुबंध की कीमत छह रुपये यानी 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,469 रुपये प्रति बैरल रह गयी। इसमें 4,492 लॉट के लिये कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड का भाव 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 61.58 डॉलर प्रति बैरल चल रहा था जबकि ब्रेंट क्रूड का भाव 0.15 प्रतिशत की तेजी के साथ 65.47 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर था।

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर बोले धर्मेंद्र प्रधान- GST के तहत लाने का प्रयास जारी

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में आए दिन पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) के दामों में भारी उछाल देखा जा रहा है। ईंधन की बढ़ती कीमत को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार (Modi Government) पर हमला बोल रहा है। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के कारण दाम बढ़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल-डीजल को जल्द ही जीएसटी के तहत लाने का प्रयास जारी है।

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर बोले धर्मेंद्र प्रधान

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के कारण दाम बढ़े हैं। कोरोना वायरस की वजह से मांग कम होने से आपूर्ति में भी कटौती हुई थी। उन्होंने कहा कि तेल की आपूर्ति करने वाले देशों ने वादा किया था कि हम जनवरी-फरवरी में आपूर्ति को पहले की स्थिति में ले आएंगे, उनके नहीं लाने के कारण ये स्थिति बनी है। एशिया के सारे देश उत्पादन बढ़ाने के लिए दबाव बना रहे हैं, हमें लगता है कि इससे कुछ फर्क आना चाहिए।

पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये जीएसटी काउंसिल का विषय है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री की तरफ से हम पहले दिन से इसके लिए अनुरोध कर रहे हैं। धीरे-धीरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी की ओर ले जाना पड़ेगा।

सरकार ने भी जताई चिंता

इससे पहले रविवार को केन्द्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि फ्यूल की कीमत बढने की 2 मुख्य वजह हैं। पहला, इंटरनैशनल मार्कीट ने फ्यूल उत्पादन कम कर दिया है और दूसरा, ज्यादा फायदे के लिए मैन्यूफैक्चरिंग देश कम फ्यूल का उत्पादन कर रहे हैं। इससे उपभोक्ता देशों को दिक्कत हो रही है। देश में 22 फरवरी को लगातार दूसरे दिन भी फ्यूल की कीमतें स्थिर रहीं। राजधानी दिल्ली में पैट्रोल 90.58 रुपए प्रति लीटर और डीजल 80.97 रुपए पर बिक रहा है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल

गौरतलब है कि देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई हैं। ज्यादातर राज्यों में पेट्रोल की कीमत पहली बार 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गई है। आने वाले दिनों में भी कीमत घटने की संभावना नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल आने के बाद घरेलू बाजार में भी कीमतों पर असर पड़ा है। गौरतलब है कि भारत अपनी तेल संबंधी 85 प्रतिशत जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। अमेरिका में ऊर्जा संकट के चलते इस सप्ताह ब्रेंट तेल की कीमत 65 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई थी। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की महंगाई को लेकर सरकार भले ही दुहाई दे रही है, लेकिन हकीकत यह है कि हम 29.34 रुपये लीटर वाले पेट्रोल की कीमत 88 रुपये से

अधिक चुका रहे हैं।

दिल्ली में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम

बता दें कि राजधानी दिल्ली में तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से आम आदमी के बजट पर खासा असर पड़ रहा है। आज एक बार फिर से राजधानी में तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्रमश 90.83 रुपये प्रति लीटर (25 पैसे की वृद्धि) और 81.32 रुपये प्रति लीटर (35 पैसे की वृद्धि) पर हैं।

जानें पेट्रोल डीजल में कितनी लगती है एक्साइज ड्यूटी

वहीं डीजल की बात करें तो इसका बेस प्राइस दिल्ली में 1 फरवरी को केवल 30.55 रुपये था, जबकि इस दिन मार्केट में यह 76.48 रुपये लीटर बिक रहा था। दरअसल भारत में डीजल और पेट्रोल पर केंद्र सरकार जहां एक्साइज ड्यूटी के रूप में हर लीटर पर 32 रुपये से अधिक वसूल ती है, तो राज्य सरकारें वैट और उपकर (सैस) लगाकर लोगों की जेब से अपना खजाना भर रही है।

आरजीपीपीएल में गेल की 25.1 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी एनटीपीसी

नयी दिल्ली। एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने मंगलवार को कहा कि उसने रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लि. (आरजीपीपीएल) में गेल की 25.51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने को लेकर शेयर खरीद समझौता किया है। आरजीपीपीएल को दाभोल परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इस सौदे के पूरा हो जाने के बाद एनटीपीसी की आरजीपीपीएल में 86.49 प्रतिशत हिस्सेदारी हो जाएगी। इससे पहले, जनवरी में कंपनी ने आरजीपीपीएल में उसको कर्ज दे रखे वित्तीय संस्थानों से 35.47 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की थी। शुरू में एनटीपीसी और गेल दोनों ने दाभोल परियोजना में 25.51-25.51 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। बीएसई को दी गयी सूचना के अनुसार, "एनटीपीसी लि. ने रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लि. में गेल की 25.51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने तथा कोंकण एलएनजी लि. में एनटीपीसी की 14.82 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को लेकर 23 फरवरी, 2021 को गेल (इंडिया) लि. के साथ शेयर खरीद समझौता किया।" समझौतों के तहत शेयरों के हस्तांतरण के साथ एनटीपीसी कोंकण एलएनजी लि. से बाहर हो जाएगी जबकि एनटीपीसी की आरजीपीपीएल में हिस्सेदारी बढ़कर 86.49 प्रतिशत हो जाएगी। आरजीपीपीएल का गठन आठ जुलाई, 2005 को हुआ। इसकी प्रवर्तक एनटीपीसी और गेल (इंडिया) लि. है। कंपनी का गठन दाभोल पावर कंपनी प्रोजेक्ट की

संपत्ति को लेने और उसे पटरी पर लाने के लिये हुआ था।

साइबर क्राइम के खिलाफ आरबीआई को मिला 'वायरस' का साथ

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बढ़ती साइबर धोखाधड़ी तथा ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन में आई कई गुना तेजी के बीच लोगों को जागरूक करने के लिए पंजाबी रैपर वायरस से गठजोड़ किया है। रिजर्व बैंक ने सप्ताहांत पर इस मुहिम को अपने ट्विटर हैंडल से आधिकारिक तौर पर जारी किया। इस मुहिम में लोकप्रिय पंजाबी गायक व रैपर वायरस को लिया गया है। रैपर वायरस को अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की फिल्म लक्ष्मी के लिए 'बम भोले' गाने को नया रूप देने के बाद खासी लोकप्रियता मिली है। रिजर्व बैंक ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलोअर वाला केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय है। इस महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के चलते ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में काफी तेजी आई है। इसके साथ ही साइबर क्राइम के मामले भी बढ़े हैं।

भारत को कच्चा तेल और गैस एक्सपोर्ट को लेकर अमेरिका से आया बड़ा बयान

न्यूयॉर्क। एजेंसी

जीवाश्म ईंधन के प्रति राष्ट्रपति जो बाइडेन के विरोध के बावजूद, अमेरिका सतत ऊर्जा विकास का समर्थन करते हुए भारत को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति जारी रखेगा। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने यह जानकारी दी। उन्होंने सोमवार को यह पूछे जाने पर कि क्या बाइडेन प्रशासन निर्यात जारी रखेगा, तो इसके जवाब में प्राइस ने कहा कि भारत के साथ सामरिक ऊर्जा साझेदारी के तहत हमारा व्यापक सहयोग मजबूत है और यह तब भी बढ़ता रहेगा जब प्रशासन जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को प्राथमिकता देगा। जलवायु परिवर्तन से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ, बाइडेन जीवाश्म ईंधन से जुड़े विदेशी पारिस्थितिकी की समीक्षा कर रहे हैं और एक बड़े कदम में कनाडा से अमेरिका तेल लाने के लिए विवादास्पद कीस्टोन पाइपलाइन परियोजना को रद्द कर दिया।

अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका कच्चे तेल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया है, जिसने 2020 तक नवंबर के दौरान लगभग 8.4 करोड़ बैरल और लगभग 11,500 करोड़ क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का निर्यात किया है। प्राइस ने कहा कि जब यह ऊर्जा सहयोग में अधिक व्यापक रूप से आता है, तो मैं कहूंगा कि अमेरिका-भारत ऊर्जा साझेदारी सतत ऊर्जा विकास का समर्थन करती है। यह 21वीं सदी की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करती है। उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करता है और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बढ़ावा देता है।

ऊर्जा क्षेत्र में भारत-अमेरिका का सहयोग 2017 में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में बढ़ना शुरू हुआ, जो भारत को तेल और गैस निर्यात बढ़ाने और ईरान पर निर्भरता से दूर करने के लिए उत्सुक थे। अमेरिका-भारत ऊर्जा सहयोग ने स्वच्छ ऊर्जा पर जोर देने के साथ पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन में जोर पकड़ना शुरू किया लेकिन ट्रंप प्रशासन के तहत, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन मसले से दूरी बना ली थी, अमेरिका से जीवाश्म ईंधन निर्यात ने रफ्तार पकड़ी।

ट्रांसपोर्टरों ने बढ़ाया किराया, बढ़ सकती है महंगाई की मार

नई दिल्ली। एजेंसी

डीजल के दाम में कमी नहीं थमी तो महंगाई की मार बढ़ सकती है। डीजल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते ट्रांसपोर्टरों ने कुछ सेक्टरों में मालभाड़े में 20 फीसदी तक बढ़ोतरी कर दी है। ट्रांसपोर्टरों के अनुसार अभी इंफ्रा सेक्टर, माइनिंग और कच्चे माल समेत कुछ सेक्टरों की मालभाड़े में बढ़ोतरी की गई है। अगर सरकार ने डीजल के दाम कम करने के उपाय नहीं किए तो सभी सेक्टरों में मालभाड़ें में बढ़ोतरी की जाएगी। इससे दैनिक इस्तेमाल की चीजों और खाद्य वस्तुओं के दाम पर असर पड़ सकता है। चीजें महंगी हो सकती है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल नवीन गुप्ता ने एनबीटी से बातचीत में कहा कि हमने सरकार से कहा है कि डीजल पर एक्साइज और वैट कम किया जाए। डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। डीजल की मूल्य समीक्षा रोज नहीं, हर पखवाड़े की जाए। अगर इस बारे में सरकार ने जल्दी कुछ नीतिगत कदम नहीं उठाए तो हम कड़े कदम उठाने पर मजबूर होंगे। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि पिछले डेढ़ महीने में डीजल के दाम 30 फीसदी बढ़े हैं। अभी ट्रांसपोर्टर्स ने कुछ सेक्टरों में माल भाड़ा 20 फीसदी बढ़ाया है। इसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। सरकार ने अगर डीजल में कम से कम 20 रुपये प्रति लीटर तक कीमतें नहीं घटाई तो आगे स्थिति और बिगड़ेगी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि लागत बढ़ने के चलते भाड़ा बढ़ाना उनकी मजबूरी है।

जीडीपी ग्रोथ होगी प्रभावित

इस बीच कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट एस एम सुरेश का कहना है कि ट्रांसपोर्टरों की बातों से लग रहा है कि उन्होंने मालभाड़ा बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की जो मजबूरियां है, उससे साफ लग रहा है कि सरका के पास डीजल की कीमतें कम करने की गुंजाइश कम है। ऐसे में सभी सेक्टरों में मालभाड़ा बढ़ा तो इसका सीधा असर रोजमर्रा के जरूरी सामान के साथ खाद्य उत्पादों पर भी पड़ेगा। इससे दोहरी मार पड़ेगी। एक तो खाद्य वस्तुएं महंगी होंगी, इससे आम आदमी के किचन का बजट प्रभावित होगा। दूसरे खरीदारी कम होने से जीडीपी ग्रोथ पर इसका सीधा असर होगा। वहीं इंडस्ट्री चैंबर एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल दीपक सूद का कहना है कि इस वक्त रीटेल महंगाई को काबू में रखना जरूरी है। अगर रीटेल महंगाई बढ़ गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा।

अंडों के निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रमाण-पत्र अनिवार्य करने का प्रस्ताव

नयी दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय ने अंडों और उसके उत्पाद के निर्यात के नियमों का एक मसौदा जारी किया है जिसके तहत माल की खेप विदेश भेजने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच कराना जरूरी होगा। मंत्रालय ने इस आदेश के मसौदे पर लोगों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। मसौदा आदेश के तहत अंडे और अंडे के उत्पादों की किसी खेप का

निर्यात तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक उसको लेकर लागू मानकों के अनुपालन की पुष्टि नहीं हो जाती। साथ ही इस पर मनोनीत एजेंसी द्वारा जारी निर्यात योग्य प्रमाणपत्र की जरूरत होगी। मंत्रालय के 22 फरवरी के आदेश के तहत, ''...केंद्र सरकार ने निर्यात निरीक्षण परिषद के साथ विचार-विमर्श के बाद यह तय किया है कि भारत के निर्यात व्यापार को गति देने के लिये यह जरूरी है...यह अधिसूचित किया जाता है कि अंडा और अंडे के उत्पादों का निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण अथवा दोनों पर निर्भर करेगा। यह सब निर्यात से पहले किया जाएगा।'' इसमें यह भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का इस मामले में कोई आपत्ति या सुझाव है तो वह उसे निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज सकता है।

शेराटन ग्रैंड पैलेस को मिला 'लक्ज़रीयस एंड ग्रैंड फाइव स्टार प्रॉपर्टी' का खिताब

ओपनिंग के बाद पहली बार जीता 'लक्ज़रीयस एंड ग्रैंड फाइव स्टार प्रॉपर्टी' का खिताब

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

शेराटन ग्रैंड पैलेस ने 'लक्ज़रीयस एंड ग्रैंड फाइव स्टार प्रॉपर्टी' का खिताब जीता है। यह खिताब शेराटन ग्रैंड पैलेस को रेड एफएम द्वारा उनके रेड अचीवर्स अवार्ड्स 2021' के तहत प्रदान किया गया है। रेड एफएम ने हर केटेगरी में से किसी एक को चुना है जिसमे होस्पिटेलिटी केटेगरी में 'लक्ज़रीयस एंड ग्रैंड फाइव स्टार प्रॉपर्टी' के लिए शेराटन ग्रैंड पैलेस को चुना गया। शामिल होने वाले होटल को अलग-अलग मापदंडो पर परखा जाता है, जिसमें प्रमुख तौर पर मेहमानों का फीडबैक शामिल होता है।

शेराटन ग्रैंड पैलेस के जनरल मैनेजर रोहित बाजपाई ने बताया की, ' यह होटल खुलने के बाद का पहला अवार्ड है जो हमें मिला है और इस अवार्ड से हम और पूरी शेराटन ग्रैंड पैलेस की टीम बहुत उत्साहित है। शेराटन ग्रैंड पैलेस में हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है की जनता को सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्रदान करें, यह पुरस्कार हमारे होटल के सभी मेहमानों का ही हमारे प्रति प्रेम है जिसकी वजह से हमें यह अवार्ड मिला हैं। शेरोटन ग्रैंड पैलेस मध्य भारत का एक आदर्श वेडिंग डेस्टिनेशन बन चूका है और यहाँ की लक्ज़रीयस और 5 स्टार सर्विस ने सभी गेस्ट का दिल जीता है जो इस अवार्ड से सिद्ध हो चूका है।'

लैपटॉप, टैबलेट, पीसी के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए पीएलआई योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी तथा सर्वर के विनिर्माण को प्रोत्साहन के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है। पीएलआई योजना के जरिये सरकार का इरादा घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने का है। इन हाई-टेक आईटी हार्डवेयर गैजट्स के लिए पीएलआई योजना को हरी झंडी से पहले पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार उपकरण विनिर्माण के लिए 12,195 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी थी। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि मंत्रिमंडल

ने आईटी हार्डवेयर के लिए 7,350 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर आएंगे। प्रसाद ने कहा कि यह योजना भारत को इन उत्पादों के बड़े विनिर्माण केंद्र के रूप में पेश करेगी। इससे निर्यात बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। योजना के तहत चार साल के दौरान भारत में इन उत्पादों के विनिर्माण के लिए 7,350 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। चार साल में इन उत्पादों का विनिर्माण 3.26 लाख करोड़ रुपये और निर्यात 2.45 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

नया श्रमिक कोडः साप्ताहिक कार्य अवधि को लेकर नीतिगत असमंजस दूर करने की पहल

नई दिल्ली। एजेंसी

यह आम धारणा है कि जब तक किसी कार्य को अपना समझकर पूरी लगन व मेहनत से नहीं किया जाएगा, तबतक उसकी सफलता संदिग्ध रहेगी। ऐसे में साप्ताहिक कार्यावधि के बारे में जो प्रशासनिक नीतिगत असमंजस दृष्टिगोचर हो रहा है, वह कतिपय आयामों में व्यक्तिगत, संस्थागत और राष्ट्रगत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी बड़े अवरोधक की तरह आंका जाने लगा है।

सवाल है कि जब सप्ताह में 6 दिन और 48 घण्टे की कार्यावधि पहले से ही निर्धारित है, तब उसे केंद्रीय सेवाओं में पहले 5 दिन करना और अब विभिन्न निजी-सरकारी इकाइयों को 4 दिन के कार्य सप्ताह की अनुमति देने के लिए सेंट्रल द्वारा एक नए श्रम कोड की रूपरेखा तैयार करने हेतु आम राय विकसित करना किसके लिए फायदेमंद होगा और किसके लिए हानिकारक, यह वक्त बताएगा, मैं नहीं।

लेकिन यह अनुभूत सत्य है कि जिस तरह से कोई किसान या कारोबारी पूर्ण मनोयोग से 24 घण्टे, सातों दिन अपने कार्य को करता रहता है, वैसा ही माहौल देने की बजाए कहीं 7 दिन में 6 दिन, कहीं 5 दिन और कहीं 4 दिन और कुल मिलाकर 48 घण्टे काम करवाने की बात कानूनी तौर पर जायज ठहराना किसी किसी पेशे के लिए उचित है तो किसी किसी पेशे के लिए अनुचित भी। ऐसे में बेहतर यही होगा कि पूरे राष्ट्र के लिए एक समान श्रम कानून बने जिसमें न्यूनतम कार्यावधि, कार्यदिवस, वेतनमान व अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में ज्यादा तफरका नहीं दिखाई दे। क्योंकि अब तक बने श्रम कानूनों का अनुपालन न तो सरकारी संस्थाओं में पूरी ईमानदारी पूर्वक किया गया और न ही निजी संस्थानों में। संगठित और असंगठित क्षेत्रों की जो नीतिगत विषमताएं व विवशताएं हैं, सो अलग।

इसलिए सरकार से उम्मीद है कि वह टुकड़े टुकड़े वाली सोच से बाहर निकले और अपने ए ग्रेड के अधिकारियों व बी, सी, डी ग्रेड के पदाधिकारियों व कर्मचारियों के बारे में विभिन्न मामलों में व्याप्त चौड़ी खाई को पाटने की व्यापक पहल करे। क्योंकि जब सबका मत समान है तो फिर शिक्षा व पेशागत आधार पर व्याप्त कानूनी विभेदों व आर्थिक ऊंच-नीच की अवधारणा को भी समाप्त करना नया इंडिया की अवधारणा को अधिक फलीभूत करेगा। यूं तो प्रस्तावित श्रमिक कोड में सरकार ने श्रमिकों को राज्य बीमा निगम के माध्यम से श्रमिक कोड के तहत निः शुल्क चिकित्सा जांच प्रदान करने का भी प्रस्ताव दिया है। दरअसल, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने चार नए श्रम कोड के लिए नियमों को अंतिम रूप देने

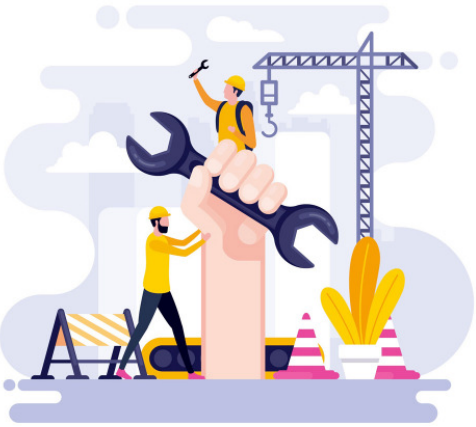

के लिए प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की संभावना है। इस बारे में श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा ने हाल ही में घोषणा की कि प्रस्तावित श्रम संहिता कंपनियों को सप्ताह में चार दिन काम करने की सुविधा प्रदान कर सकती है, लेकिन सप्ताह में 48 घंटे काम करने की सीमा भी सीमित रहेगी।

ऐसा इसलिए कि सरकार ट्रेड यूनियनों द्वारा 12 घंटे के दैनिक कार्य शिफ्ट यानी 4 दिन की साप्ताहिक कार्यावधि और शेष तीन दिनों के पूर्ण भुगतान पर की गई आपत्तियों पर विचार कर रही है। श्री चंद्रा ने दो टूक कह दिया कि, 'देखें, एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे का काम होगा। यदि कोई दिन में 8 घंटे काम करता है, तो प्रति सप्ताह 6 कार्य दिवस होंगे। यदि कोई कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए प्रति दिन 12 घंटे काम अवधि निर्धारित करती है तो इसका साफ मतलब है चार दिन का काम और तीन दिन छुट्टियां।'

शासन-प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि दैनिक कामकाज के घंटे बढ़ाए जाते हैं, तो आपको श्रमिकों को समान छुट्टियां भी देनी होंगी। यदि घंटे बढ़ाए जाते हैं तो 5 या 4 कार्य दिवस ही होंगे। अब इस जटिल मसले पर कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति दी जाएगी कि क्या उचित है उनके लिए और क्या नहीं। क्योंकि यह तय है कि कोई भी दिन में 12 घंटे लगातार काम नहीं कर पाएगा। मंत्रालय के मसौदे के मुताबिक, नए श्रम कानून किसी भी तरह से मजदूरों और कर्मचारियों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। इसलिए प्रस्तावित नियम और विनियम में अब काम के घंटों से संबंधित प्रावधानों को स्पष्टता पूर्वक तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि, अभी तक कोई अंतिम शब्द नहीं है। एक बार नियम तैयार हो जाने के बाद, चीजें और अधिक स्पष्ट हो जाएंगी। मंत्रालय यह आश्वस्त करना चाहता है कि प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों का शोषण नहीं कर पाएंगे। किसी भी कीमत पर नहीं।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से श्रमिकों को मुफ्त चिकित्सा जांच प्रदान करने का भी प्रस्ताव रखा है। वास्तव में, स्पष्ट सरकारी प्रावधानों से पहली बार, देश में सभी प्रकार के श्रमिकों को अब न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। वहीं, प्रवासी श्रमिकों के लिए नई योजनाएं लाई जा रही हैं। इसके अलावा, सभी प्रकार के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भविष्य निधि की सुविधा दी जाएगी। संगठित और असंगठित क्षेत्र- ईएसआई द्वारा कवर किए जाएंगे। और तो और, महिलाओं को सभी प्रकार के व्यापार में काम करने की अनुमति दी जाएगी, और रात की पाली करने की अनुमति दी जाएगी।

दरअसल, सरकार ने मजदूरी, औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कामकाजी परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा पर नए श्रमिक कोड के कार्यान्वयन का जो फैसला किया है, उससे सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यही नहीं, इससे सम्बन्धित पोर्टल पर नामांकित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा भीम योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत आकस्मिक और विकलांगता कवर के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त कवरेज के प्रोत्साहन के साथ प्रदान किया जाएगा। बता दें कि श्रम मंत्रालय ने इस साल एक अप्रैल से चार श्रम संहिता को एक बार में लागू करने की परिकल्पना की थी। जिसके मद्देनजर मंत्रालय ने 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को मजदूरी, औद्योगिक संबंधों, सामाजिक सुरक्षा और ओएसएच पर चार व्यापक कोड में समाहित करने का फैसला किया, जो कि अब अंतिम चरण में है।

चीन, भारत, रूस जैसे बड़े कार्बन उत्सर्जकों को कदम उठाने एवं उत्सर्जन में कमी लाने की जरूरत : केरी

संयुक्त राष्ट्र। एजेंसी

जलवायु पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने कहा है कि चीन, भारत, रूस और जापान समेत विश्व के बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों को 'वास्तविक कदम उठाने' एवं ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। केरी ने सभी देशों से आह्वान किया कि वे जलवायु परिवर्तन से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता बढ़ाएं। उल्लेखनीय है कि केरी ने यह बात जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के लिए हुए पेरिस समझौते में अमेरिका की वापसी पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में कही जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतेनियो गुतेरस भी मौजूद थे।

केरी ने कहा, ''हमें जरूरत है कि अमेरिका और प्रत्येक देश प्रतिबद्ध हो कि वे वर्ष 2050 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते पर चलेंगे। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे देशों द्वारा केवल इच्छा व्यक्त करने और कहने से होगा कि 'देखो, हम प्रतिबद्ध हैं। हम यहां पर है। हां, हम 2050 तक करेंगे।' यह काम नहीं करेगा, इससे कटौती नहीं होगी। यह वह रास्ता नहीं हैं जिसके साथ हम ग्लासगो जाना चाहते हैं।'' उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन सीओपी26 इस साल नवंबर में ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। सीओपी26 सम्मेलन पेरिस समझौते

और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन मसौदा कानून के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्रवाई को गति देने में सभी पक्षों को साथ लाएगा।

केरी ने कहा, ''एक देश के तौर पर ग्लासगो जाने पर उनके पास वास्तविक योजना होनी चाहिए जैसे आखिर हमें अब क्या करने की जरूरत है। अगले 10 साल में हम क्या कदम उठाएंगे? सच्चाई है कि यह सभी को करना है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा (कार्बन)उत्सर्जक है और उसे वर्ष 2020 से 2030 के प्रयास का हिस्सा बनने की जरूरत है।'' उन्होंने कहा, ''भारत को इसका हिस्सा होने की जरूरत है, रूस को हिस्सा होने की जरूरत है। इसी तरह जापान...और प्रमुख 17 उत्सर्जक देशों को वास्तव में कदम उठाने एवं उत्सर्जन को कम करने की शुरुआत करने की जरूरत हैं'' केरी ने कहा कि यह चुनौती है, इसका मतलब है कि सभी देशों ने जो साहसिक एवं प्राप्त करने वाले लक्ष्य तय किए हैं उनके लिए घर में कार्य करने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 40 प्रतिशत तक बढ़ाकर एवं वन क्षेत्र में विस्तार कर वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35 कटौती का लक्ष्य रखा है जिससे वातावरण में 2.5 से तीन अरब टन कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी। अमेरिका आधिकारिक रूप से जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते में दोबारा शामिल हो गया है। इससे पहले, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को समझौते से अलग कर लिया था।

भारत को निर्यात बढ़ाने को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने की जरूरत : अमिताभ कान्त

नयी दिल्ली। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कान्त ने कहा है कि भारत को निर्यात बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इससे दूरसंचार, वाहन, बैटरी स्टोरेज उपकरण और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को फायदा मिलेगा। अमिताभ कान्त ने मंगलवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की 'भारत में विदेश व्यापार और निवेशः रणनीतिक सुधारों के जरिये महत्वपूर्ण अवसरों का दोहन' रिपोर्ट जारी किए जाने के मौके पर कहा कि देश अब बदलाव के मुहाने पर है। सीआईआई की ओर से जारी बयान में अमिताभ कान्त के हवाले से कहा गया है, '' भारत को अपना निर्यात बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।''' उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के निर्यात से दूरसंचार, वाहन, बैटरी स्टोरेज उपकरण और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि महामारी के बाद लागू सुधार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मददगार होंगे। नीति आयोग के सीईओ ने कहा, ''आज भारत वैश्विक निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। सुधार प्रक्रियाओं की वजह से ही महत्वपूर्ण संकेतकों मसलन जीडीपी, एफडीआई और व्यापार में तेजी से सुधार हुआ है।''

उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट में उन उपायों का जिक्र है जिनके जरिये भारत को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रिटेन के उप व्यापार आयुक्त-दक्षिण एशिया आर हैरिस ने कहा कि ब्रिटेन-भारत के संबंधों में व्यापार और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। हैरिस ने कहा कि ब्रिटेन और भारत की सरकारें व्यापारिक भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे और बाजार पहुंच की अड़चनें दूर होंगी।

तेल कारोबार में हिस्सेदारी बेचने के लिए रिलायंस ने किया यह अहम काम

नई दिल्ली। मुकेश अंबानीकी अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने तेल-से-रसायन कारोबार के पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई में डिमर्जर की रूपरेखा घोषित कर दी है। कंपनी ने शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स से इसके लिए मंजूरी मांगी है। इससे कंपनी को सऊदी अरामको जैसे ग्लोबल इनवेस्टर्स को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि उसे अगले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही तक इसके लिए जरूरी मंजूरी मिल जाएगी। आरआईएल ने एक्सचेंजेज की दी जानकारी में कहा है कि ऑयल टु केमिकल्स कारोबार के पुनर्गठन से उसे ओटुसी वैल्यू चेन में अवसरों का फायदा उठाने का मौका मिलेगा और डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम इनवेस्टर कैपिटल के डेडिकेटेड पूल्स को आकर्षित करेगी। ईटी ने सबसे पहले 20 फरवरी को रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में डिटेल से जानकारी दी थी। कंपनी पर नजर रखने वाले कई लोग इसे दीर्घकालिक उत्तराधिकार योजना (Long term succession planning) की दिशा में उठाया गया कदम मान रहे हैं।

सऊदी अरामको से बातचीत

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सऊदी अरामको जैसी कंपनियों को हिस्सेदारी की संभावित बिक्री के लिए तेल-से-रसायन व्यवसाय को अलग इकाई बनाने का काम पिछले साल शुरू किया था। कंपनी के तेल-से-रसायन व्यवसाय का मूल्यांकन 75 अरब डॉलर किया गया था। कंपनी सऊदी अरब ऑयल कंपनी (अरामको) के साथ 20 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के लिए बातचीत कर रही थी। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण यह रुक गई थी। दोनों कंपनियों के बीच एक बार फिर बातचीत का दौर शुरू हो रहा है। अप्रैल के बाद दोनों के बीच फिजिकल मीटिंग्स का दौर फि से शुरू हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तेल-से-रसायन कारोबार के लिए अलग इकाई बना रही है। कंपनी का कहना है कि इस कदम से उसे रणनीतिक साझेदारों के साथ वृद्धि के अवसरों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कंपनी की तेल-से-रसायन इकाई में परिशोधन संयंत्र, पेट्रोरसायन इकाइयां और खुदरा ईंधन विपणन कारोबार शामिल है। इसमें केजी-डी6 जैसे तेल व गैस उत्पादक क्षेत्र तथा कपड़ा व्यवसाय शामिल नहीं है।

एविएशन सेक्टर के लिए अच्छी खबर, किराये की सीमा समाप्त कर सकती है सरकार

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि गर्मियों के मौसम में घरेलू हवाई यातायात में और वृद्धि की उम्मीद के साथ सरकार उड़ानों के संबंध में अन्य पाबंदियों के साथ किरायों पर सीमा की पाबंदी को हटा सकती है। शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार नागर विमानन मंत्रालय की परामर्श समिति की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में सवालों के जवाब में पुरी ने यह भी कहा कि घरेलू हवाई यातायात दिन-ब-दिन बढ़ रहा है और अब यह करीब 3 लाख यात्री प्रतिदिन पहुंच गया है। पुरी ने संसद सदस्यों को कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों के साथ विमानन क्षेत्र के लाभ के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। बयान के अनुसार उन्होंने किराये की न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गर्मियों के दौरान घरेलू यातायात और बढ़ेगा, इसके साथ किराया दायरा और अन्य पाबंदियों को समाप्त किया जा सकता है। उड़ान योजना के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि चार दौर की बोलियां हो चुकी हैं और 700 से अधिक मार्गों की मंजूरी दी गई है।

अमेज़ॅन इंडिया ने पूर्व-सैनिकों को रोजगार के लिए भर्ती करने के लिए समझौता

महानिदेशालय पुनर्वास के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

अमेज़ॅन इंडिया ने भारत में अपने बढ़ते ऑपरेशंस नेटवर्क में पूर्व-सैनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महानिदेशक पुनर्वास (डीजीआर) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। इस साझेदारी के साथ, अमेज़ॅन इंडिया देशसेवा कर चुके पूर्व-सैनिकों के लिए वैकल्पिक कैरियर के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अपनी भर्ती जारी रखेगा। एमओयू पर लिजु थॉमस, एचआर डायरेक्टर, कस्टमर फुलफिलमेंट एवं कॉर्पोरेट, अमेज़ॅन इंडिया ऑपरेशंस और मेजर जनरल एमके सगोच, महानिदेशक, डीजीआर ने हस्ताक्षर किये।

डीजीआर के साथ एसोसिएशन अनुभवी पूर्व-सैनिकों की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने में अमेज़ॅन इंडिया को सक्षम बनाएगा, जिससे अधिक से अधिक प्रतिभाओं तक इसकी पहुंच बनेगी। पूर्व-सैनिकों के लिए अमेज़ॅन के फुलफिलमेंट सेंटर्स, सॉर्ट सेंटर्स, और डिलीवरी स्टेशनों पर रोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध होंगे, जिसमें व्यक्तिगत योगदान और प्रबंधकीय भूमिकाओं के मिले-जुले अनुभवों का इस्तेमाल होगा। इस सहयोगी प्रयास से अमेज़ॅन इंडिया के मौजूदा मिलिटरी वेटरन इम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का विस्तार होगा।

अमेज़ॅन इंडिया ऑपरेशंसकी एचआर डायरेक्टर, स्वाति रुस्तगी ने बताया कि 'हम अमेज़ॅन में अपने कार्यबल में विविधता, समानता और समावेशी माहौल को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं जहां अद्वितीय दृष्टिकोण को सम्मान दिया जाता है और इससे हमारी प्रगति में मदद मिलती है। समावेशी वातावरण के लिए हमारा दीर्घकालिक दृष्टिकोण एक संतुलित कार्यबल विकसित करना है और यह एमओयू उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।'

देश में 2020 में सौर क्षमता में 3,239 मेगावाट की वृद्धि, पांच साल में सबसे कम: रिपोर्ट

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत ने कोविड19 से प्रभावित पिछले साल 2020 में 3,239 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ा। यह पिछले साल के मुकाबले 56 प्रतिशत कम है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। मेरकॉम इंडिया रिसर्च ने मंगलवार को अपनी रिपोट में कहा कि सौर ऊर्जा क्षमता में 3,239 मेगावाट की वृद्धि पांच साल में सबसे कम है। रिपोर्ट के अनुसार, ''भारत ने 2020 में 3,239 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ा जो इससे पिछले साल 2019 के 7,346 मेगावाट के मुकाबले 56 प्रतिशत कम है।'' इसमें कहा गया है कि दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार भारत में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 39,000 मेगावाट थी। कुल जोड़ी गयी क्षमता में बड़ी परियोजनाओं की हिस्सेदारी 2,520 मेगावाट यानी 78 प्रतिशत रही। यह सालाना आधार पर 60 प्रतिशत कम है। शेष 719 मेगावाट की हिस्सेदारी छतों पर लगने वाली सौर परियोजनाओं की है।

इसमें भी 2019 के मुकाबले 22 प्रतिशत की कमी आयी है। रिपोर्ट के अनुसार बड़े आकार की सौर क्षमता वृद्धि के मामले में आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीन शीर्ष राज्य हैं। पिछले साल स्थापित कुल क्षमता इन राज्यों की हिस्सेदारी करीब 51 प्रतिशत रही। मेरकॉम कैपिटल ग्रुप के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज प्रभु ने कहा, ''भारत में 2020 में क्षमता वृद्धि पांच साल में सबसे कम है। वहीं दुनिया के अन्य प्रमुख सौर ऊर्जा बाजारों में सकारात्मक वृद्धि हुई है। भारत ने महामारी से निपटने के लिये कड़ाई से 'लॉकडाउन' लगाया था। इससे क्षेत्र को पटरी में आने में थोड़ा समय लगा। हालांकि 2021 में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।'' रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के अलावा सरकारी एजेंसियों को वितरण कंपनियों को बिजली खरीद समझौते के लिये तैयार करने में होने वाली कठिनाई है। करीब 17,000 से 18,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं बिना बिजली खरीद समझौते के हैं। इसके अलावा मोड्यूल के दाम में वृद्धि, माल ढुलाई लागत में बढ़ोतरी और कच्चे माल की लागत में तेजी अन्य अल्पकालीन चुनौतियां हैं।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टोकरेंसी पर जताई बड़ी चिंता, जानिए क्या कहा..

नई दिल्ली। एजेंसी

देश और दुनिया में बिटकॉइन (Bitcoin) जैसी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) की बढ़ती लोकप्रियता के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने इस पर चिंता जताई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी भारतीय इकनॉमी की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक ने इस बारे में अपनी चिंता से सरकार को अवगत करा दिया है। दास ने एक इंटरव्यू में यह बात कही। मोदी सरकार की योजना देश में सभी तरह की क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने और एक अधिकृत डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की है। दास ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा लेकिन आरबीआई पहले भी कई बार डिजिटल करेंसीज पर अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। उसे आशंका है कि इसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले बढ़ सकते हैं और आतंकवादियों को फंडिंग की जा सकती है। केंद्र सरकार ने साल 2018 में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के क्रिप्टोकरेंसी में कारोबार करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस रोक को हटा दिया है।

डिजिटल करेंसी जारी करने पर विचार

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हम अभी इस बारे में विचार कर रहे हैं कि देश में रुपये के डिजिटल वर्जन को जारी करने की जरूरत है या नहीं। RBI के डिप्टी गवर्नर बी पी कानूनगो ने हाल में कहा था कि आरबीआई की आंतरिक समिति डिजिटल मुद्रा जारी करने के तौर तरीकों पर गौर कर रही है और बहुत जल्दी इस बारे में अपनी सिफारिश देगी। कानूनगो ने कहा कि डिजिटल मुद्रा शुरू करने के बारे में मौद्रिक नीति समिति ने कुछ समय पहले ही घोषणा की थी। आरबीआई और सरकार की ऐसी मुद्रा को लेकर चिंता है। वे इससे जुड़े जोखिम को लेकर चिंतित हैं। पिछले कुछ सालों में डिजिटल करेंसी काफी लोकप्रिय हुई है। इसके अलावा कई देशों ने अपनी डिजिटल करेंसी भी जारी की है। इनमें इक्वाडोर, चीन, सिंगापुर, वेनेजुएला, ट्यूनीशिया और सेनेगल ने अपनी खुद की क्रिप्टोकरेंसी जारी कर दी है। एस्टोनिया, जापान, फिलिस्तीन, रूस और स्वीडन जैसे देश खुद के डिजिटल एसेट्स लॉन्च करने के विकल्प तलाश रहे हैं।

बटुक भैरव की साधना के 8 रहस्य

हिन्दू धर्म में भैरव को विशाल आकार के काले शारीरक वर्ण वाले, हाथ में भयानक दंड धारण किए हुए और साथ में काले कुत्ते की सवारी करते हुए वर्णन किया गया है। दक्षिण भारत में ये 'शास्ता' के नाम से तथा माहाराष्ट्र राज्य में ये 'खंडोबा' के नाम से जाने जाते हैं। मुख्यतः काल भैरव और बटुक भैरव की पूजा का प्रचलन है। श्री लिंगपुराण 52 भैरवों का जिक्र मिलता है।

मुख्य रूप से आठ भैरव माने गए हैं- 1.असितांग भैरव, 2. रुद्र भैरव, 3. चंद्र भैरव, 4. क्रोध भैरव, 5. उन्मत्त भैरव, 6. कपाली भैरव, 7. भीषण भैरव और 8. संहार भैरव। आदि शंकराचार्य ने भी 'प्रपञ्च-सार तंत्र' में अष्ट-भैरवों के नाम लिखे हैं। तंत्र शास्त्र में भी इनका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सप्तविंशति रहस्य में 7 भैरवों के नाम हैं। इसी ग्रंथ में दस वीर-भैरवों का उल्लेख भी मिलता है। इसी में तीन बटुक-भैरवों का उल्लेख है। रुद्रायमल तंत्र में 64 भैरवों के नामों का उल्लेख है। आओ जानते हैं भगवान बटुक भैरव की संक्षिप्त जानकारी।

बटुक भैरव :

1. 'बटुकाख्यस्य देवस्य भैरवस्य महात्मनः। ब्रह्मा विष्णु, महेशाधैर्वन्दित दयानिधे।।'- अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि देवों द्वारा वंदित बटुक नाम से प्रसिद्ध इन भैरव देव की उपासना कल्पवृक्ष के समान फलदायी है।

2. बटुक भैरव भगवान का बाल रूप है। इन्हें आनंद भैरव भी कहते हैं। उक्त सौम्य स्वरूप की आराधना शीघ्र फलदायी है। यह कार्य में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। 'महा-काल-भैरव' मृत्यु के देवता हैं। 'स्वर्णाकर्षण-भैरव' को धन-धान्य और संपत्ति का अधिष्ठाता माना जाता है, तो 'बाल-भैरव' की आराधना बालक के रूप में की जाती है। सद्-गृहस्थ प्रायः बटुक भैरव की उपासना ही करते हैं, जबकि श्मशान साधक काल-भैरव की।

3. बटुक भैरवजी तुरंत ही प्रसन्न होने वाले दुर्गा के पुत्र हैं। बटुक भैरव की साधना से व्यक्ति अपने जीवन में सांसारिक बाधाओं को दूर कर सांसारिक लाभ उठा सकता है। बटुक भैरव आराधना के लिए मंत्र है- ।।ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाचतु य कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ॐ।।

4. साधना का मंत्र : '।।ॐ ह्रीं वां बटुकाये क्षौं क्षौं आपदुद्धाराणाये कुरु कुरु बटुकाये ह्रीं बटुकाये स्वाहा।।' उक्त मंत्र की प्रतिदिन 11 माला 21 मंगल तक जप करें। मंत्र साधना के बाद अपराध-क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें। भैरव की पूजा में श्री बटुक भैरव अष्टोत्तर शत-नामावली का पाठ भी करना चाहिए।

5. एकमात्र भैरव की आराधना से ही शनि का प्रकोप शांत होता है। आराधना का दिन रविवार और मंगलवार नियुक्त है। पुराणों के अनुसार भाद्रपद माह को भैरव पूजा के लिए अति उत्तम माना गया है। उक्त माह के रविवार को बड़ा रविवार मानते हुए व्रत रखते हैं।

6. आराधना से पूर्व जान लें कि कुत्ते को कभी दुत्कारे नहीं बल्कि उसे भरपेट भोजन कराएं। जुआ, सट्टा, शराब, ब्याजखोरी, अनैतिक कृत्य आदि आदतों से दूर रहें। दांत और आंत साफ रखें। पवित्र होकर ही सात्विक आराधना करें। अपवित्रता वर्जित है।

7. सुर और सुरों के महाराज बटुक भैरव का मंदिर लखनऊ शहर के व्यस्ततम क्षेत्र केसरबाग में स्थित है। बटुक भैरव का यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। माना जाता है कि बटुक भैरव सुरों के राजा हैं, इसलिए यहां मांगी जाने वाली मन्नत भी कला, संगीत और साधना से जुड़ी होती है।

8. इस साधना से बटुक भैरव प्रसन्न होकर सदा साधक के साथ रहते हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं अकाल मौत से बचाते हैं। ऐसे साधक को कभी धन की कमी नहीं रहती और वह सुखपूर्वक वैभवयुक्त जीवन- यापन करता है। जो साधक बटुक भैरव की निरंतर साधना करता है तो भैरव बींब रूप में उसे दर्शन देकर उसे कुछ सिद्धियां प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से साधक लोगों का भला करता है।

बुधादित्य योग का मिलता है इन राशियों को लाभ

गोचर के अनुसार या कुंडली में जब भी बुधादित्य योग बना है तब 12 राशियों पर असर होता है। बुधादित्य योग का अर्थ है बुध और आदित्य यानी सूर्य और बुध ग्रह की जब एक साथ युति होती है तब यह योग निर्मित होता है।

आइए जानें विभिन्न राशियों पर असर

मेष : आपको धन प्राप्ति के योग हैं, इस राशि के लोगों को समाज में प्रतिष्ठा भी मिलेगी।

वृषभ : इस राशि के लोगों को सफलता पाने के लिए कई मौके मिलेंगे, इसके लिए मेहनत करनी होगी।

मिथुन : बहुत समय से जो आपका काम नहीं बन पा रहा, वो बनेगा।

कर्क : आप जिस करियर से जुड़े जिस कार्य को नहीं कर पा रहे, उस कार्य को करने की हिम्मत जुटा पाएंगे।

सिंह : अपने माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, आपको सफलता के कई अवसर भी मिलेंगे

कन्या : कन्या राशि के लिए यह बुधादित्य योग अच्छा है, आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं।

तुला : आपके आर्थिक हालात सुधरेंगे।

वृश्चिक : आपको अपने कार्य के लिए पसीना बहाना होगा।

धनु : समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा।

मकर : बुधादित्य योग आपको मनचाहा यश देगा।

कुंभ : यह संयोग आपको सफलता, कीर्ति और बड़ी मात्रा में धन दे सकता है।

मीन : इस राशि के लोगों के लिए बुधादित्य योग अच्छा है, खासकर कार्यक्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

विष्णु पुराणः इन कामों को अधिक देर तक करने से बचें

श्रेष्ठ जीवन के लिए विष्णु पुराण में ऐसी बातें बताई गई हैं, जिनका ध्यान रखने पर कई प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। जो लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, वे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करते हैं। यहां जानिए विष्णु पुराण में बताए गए ऐसे काम, जो जल्दी खत्म कर लेना चाहिए। इन कामों में अधिक समय नहीं लगाना चाहिएष्ठ

– नहाने का काम जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी खत्म कर लेना चाहिए। सुबह-सुबह नहाना श्रेष्ठ माना गया है और सुबह के समय वातावरण में ठंडक होती है, अतः ऐसे समय में अधिक समय तक पानी में रहना हमें बीमार कर सकता है।

– अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए जरूरी है कि हर रोज पर्याप्त नींद ली जाए। सोने का समय बहुत कम या ज्यादा होने पर स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, मोटापा बढ़ सकता है। कई लोगों के साथ समस्या होती है कि उन्हें जल्दी नींद नहीं आ पाती है, करवट बदलते रहते हैं और फिर देर रात नींद आती है। सोने में भी अधिक समय नहीं लगाना चाहिए।

– जागने के लिए सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त श्रेष्ठ बताया गया है। इस समय वातावरण साफ और पवित्र रहता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हर रोज जल्दी जागकर ध्यान-योग करने और टहलने पर शरीर निरोगी रहता है। जल्दी जागने के लिए रात को जल्दी सोना जरूरी है। अतः इन दोनों कामों भी हमें अधिक समय नहीं लगाना चाहिए।

– स्त्री-पुरुष को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि काम-क्रीड़ा यानी शय्यासेवन में अधिक समय न लगाएं। इस काम में बहुत अधिक समय लगाने से शरीर कमजोर हो सकता है। दोनों को ही स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

– व्यायाम से शरीर हष्ट-पुष्ट रहता है, शरीर की रोग प्रतिरोधी बढ़ती है, मौसमी बीमारियों से सुरक्षा होती है, लेकिन व्यायाम में बहुत अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। अधिक समय तक व्यायाम करने से थकान हो सकती है, शरीर में दर्द हो सकता है।

चूड़ियों के शुभ-अशुभ संकेत

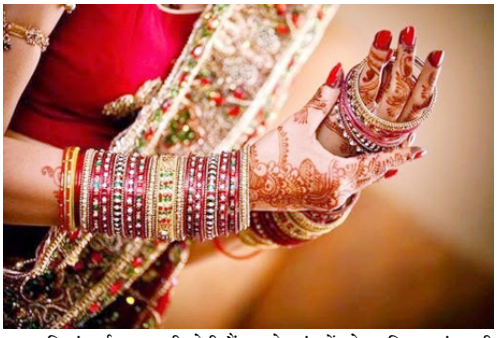

चूड़ियां कई प्रकार की होती हैं और हर एक का अपना महत्व है। सबसे पहले चूड़ियों का संदर्भ शादीशुदा स्त्रियों से जोड़कर देखा जाता है। एक विवाहित स्त्री के लिए चूड़ियां केवल श्रृंगार की वस्तु या फिर आभूषण नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे कई सारे कारण हैं। शादी के बाद स्त्रियों को सोने से बने कंगनों से अधिक कांच की चूड़ियां पहनने के लिए कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि कांच की चूड़ियां पहनने से पति और बेटे का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। अगर हम इसके वैज्ञानिक कारणों के बारे में जाने तो चूड़ियां पहनने से महिला के आसपास के वातावरण और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। चूड़ियां वातावरण में से नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचती हैं इसके साथ ही यह स्त्री के विभिन्न शारीरिक अंगों पर एक अलग सा दबाव बनती है जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है।

ये नकारात्मक भी साबित हो सकती है

आपने चूड़ियों के फायदों के बारे में तो जान लिया लेकिन इसके वितरीत प्रभाव के बारे में जानना भी जरूरी है। ऐसा तब होता है जब चूड़ियां टूटती हैं या फिर उनमें दरार आ जाती है। ऐसी मान्यता है कि चूड़ियों का टूटना उस स्त्री या उससे जुड़े लोगों के लिए एक अशुभ संकेत लेकर आता है। चूड़ियों के टूटने के साथ उनमें दरार आ जाना ही अशुभ माना जाता है। ऐसा होने पर स्त्री को चूड़ियां उतार देने की सलाह दी जाती है क्यों कि ऐसा माना जाता है कि दरार आने पर भी अगर चूड़ियों को उतारा न जाए तो महिला के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

झंडु च्यवनप्राश का प्राकृतिक गुड़ के साथ एक नया वैरिएंट

बहुमूल्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ बनाया गया, झंडु च्यवनप्राश अवलेह (गुड़)

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

इमामी समूह का, 100 साल से अधिक वर्षों का विश्वसनीय ब्रांड झंडु; भारत के बाजार में पहली बार झंडु च्यवनप्राश अवलेह का एक नया संस्करण 'जैग्गरी' (गुड़), जो कि अधिक पौष्टिक है। 39 बहुमूल्य आयुर्वेदिक जड़ी- बूटियों के साथ बनाया गया झंडु च्यवनप्राश अवलेह जैग्गरी (गुड़), प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ, सारंगधारा संहिता से लिया गया है। इसमें रिफाइंड सुगर (व्हाइट शुगर / टेबल शुगर) बिल्कुल ही नहीं है। यह प्राकृतिक गुड़ मिला कर बनाया जाता है। वैज्ञानिक रूप से, यह प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए के लिए 2X प्रमाणित है।

प्राकृतिक गुड़ शरीर को आवश्यक विटामिन और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने के लिए जाना जाता है । यह एंटी-ऑक्सीडेंट को बढ़ाने और श्वसन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। स्वास्थ्य और पोषण के दृष्टिकोण से, गुड़ को सार्वभौमिक रूप से परिष्कृत चीनी (व्हाइट शुगर / टेबल शुगर) से अधिक स्वास्थ्यप्रद विकल्प माना जाता है, जो कम पोषण-मान के कारण, कोई बड़ा स्वास्थ्य लाभ नहीं देती हैं।

झंडु की नई पेशकश के बारे में जानकारी देते हुए, इमामी लिमिटेड के निदेशक, श्री हर्ष वी. अग्रवाल ने कहा कि 'वर्तमान में, उपभोक्ताओं की जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली पर ध्यान देने के कारण, लोग, प्राकृतिक आयुर्वेदिक समाधानों के संबंध में, जिस पर वे सुरक्षित होने का भरोसा कर सकें, अधिक सजग-सचेत हो गए हैं।' उन्होंने बताया कि 'च्यवनप्राश एक बहुत ही लोकप्रिय आयुर्वेदिक उत्पाद है जो भीतर से प्रतिरक्षा को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। झंडु च्यवनप्राश अवलेह जैग्गरी (गुड़) भारत में पहला च्यवनप्राश ब्रांड है जो उपभोक्ताओं को चीनी के बदले गुड़ का स्वस्थ विकल्प देगा। हमारे जीएमपी प्रमाणित संयंत्र में उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ निर्मित, झंडु च्यवनप्राश अवलेह जैग्गरी (गुड़), गुड़ की प्राकृतिक अच्छाई प्रदान करेगा और बिना किसी दुष्प्रभाव के, परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, ऊर्जा और प्रतिरक्षा स्तर में सुधार करेगा।'

ESI लाभार्थियों के लिए खुशखबरी!

पैनल में शामिल प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हो जाएगा इलाज

नई दिल्ली। ESI (कर्मचारी राज्य बीमा) स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अगर ईएसआई लाभार्थी के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में अगर ईएसआईसी अस्पताल नहीं है तो वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में इलाज के लिये जा सकता है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी। श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार नए क्षेत्रों में भी ईएसआई योजना का विस्तार करने के परिणामस्वरूप ईएसआई लाभार्थियों की संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है।

ऐसे में अब ईएसआई सदस्यों को उनके अपने आवास के आसपास ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे के विस्तार और उसे सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है, ''इस समय कुछ क्षेत्रों में ईएसआई के अस्पताल या औषधालय या इन्श्योर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (आईएमपी) के 10 किलोमीटर के दायरे में न होने के चलते ईएसआई लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। ऐसे क्षेत्रों में ईएसआई लाभार्थियों को अब देश में ईएसआईसी के पैनल में शामिल अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए लाभार्थी को किसी ईएसआईसी अस्पताल या औषधालय से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।''

मुफ्त में ओपीडी सेवाएं लेने के लिए क्या करना होगा

मंत्रालय के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में ईएसआई लाभार्थियों को ईएसआई के पैनल में शामिल अस्पताल में ओपीडी (बाह्य मरीज विभाग) सेवाओं को मुफ्त प्राप्त करने के लिए वहां जाना होगा और अपना ईएसआई ई-पहचान पत्र/स्वास्थ्य पासबुक के साथ आधार कार्ड/सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।'' ऐसे लाभार्थी को ओपीडी में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं के लिए किए गए भुगतान को वापस लेने की सुविधा होगी। यह सुविधा पाने के लिए लाभार्थी को औषधालय एवं शाखा कार्यालय या ईएसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय जाना होगा। बयान के अनुसार यदि लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है तब पैनल में शामिल अस्पताल को 24 घंटों के भीतर ऑनलाइन माध्यम से ईएसआई के प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी ताकि लाभार्थी को नकद रहित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सके।

मसालों की बिक्री में आई तेज गिरावट, व्यापारी आवाक

नई दिल्ली। एजेंसी

पिछले साल अप्रैल-मई में जब कोरोना के मामलों में तेज इजाफा हो रहा था तो रसोई में इस्तेमाल होने वाले मसालों की बिक्री खूब बढ़ी थी। लोगों ने इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर मसालों की जमकर खरीदारी और सेवन किया। अब मसालों की सेल अचानक गिर गई है। मसालों की बिक्री घटने की वजह लोगों की आमदनी में कमी होना बताया जा रहा है।

20 फीसदी भी नहीं रही बिक्री

नॉर्दन स्पाइसेज ट्रेडर्स असोसिएशन के प्रेजिडेंट रविंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि मौजूदा समय में सामान्य से 20 फीसदी सेल भी नहीं बची है। अमूमन फरवरी का महीना मसालों के लिए अच्छा माना जाता है। यूं तो मार्च में क्लोजिंग की वजह से सेल डाउन होती थी, लेकिन अप्रैल में फिर बिक्री बढ़ जाती थी। इन दिनों मसालों की सेल घटने की वजह समझना मुश्किल हो रहा है। मसाले तो रोजमर्रा उपयोग में लाए जाते हैं। सब्जी और दाल हर कोई खाता है। ट्रेडर्स को लगता है कि फाइनेंशियल पॉजिशन खराब होने की वजह से बिजनेस मंदा पड़ा है। लोगों के पास पैसा नहीं है। बाजार में गिने-चुने ग्राहक ही पहुंच रहे हैं।

जिसे उधार में मसाले दिए वह पैसा नहीं लौटा रहा

अग्रवाल का कहना है कि जिन कारोबारियों को उधार में माल दिया है, वह भी पैसा नहीं लौटा पा रहा है। खारी बावली के होल सेल मार्केट में इस समय बड़े ऑर्डर नहीं हो रहे हैं। बाहर के व्यापारी भी दिल्ली से आधा माल ही खरीद रहे हैं। इंटरनेट के जमाने में दूसरे शहरों के बिजनेसमैन सीधा कंपनियों से माल बुक कर रहे हैं। थोक बाजारों में तो उधार खरीदारी के लिए ट्रेडर्स आते हैं। जीएसटी के मौजूदा प्रावधानों से भी व्यापारी परेशान हैं, क्योंकि इसमें ईमानदार कारोबारियों को ही प्रताड़ित किया जाता है।

बाजार में हर आइटम की डिमांड हुई कम

खारी बावली सर्व व्यापार मंडल के चेयरमैन राजीव बत्रा का कहना है कि अब लोग उतने ही मसाले खरीद रहे हैं, जितनी जरूरत है। कोरोना संक्रमण जब तेजी से फैल रहा था, उस दौर में लोग खाने-पीने का सामान इकट्ठा कर रहे थे। अब वैक्सीन भी आ गई है। लोगों में भी भय कम हो गया है। इस वजह से डिमांड घटी है। वैसे भी बाजार में हर आइटम की डिमांड कम हुई है। मार्केट में बेरोजगारी बढ़ी है। जिन लोगों ने कर्मचारियो को काम पर रखा है, वे सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। आय का स्त्रोत कम हो गया है, खर्चे बढ़ रहे हैं। इसका असर बाजार में दिख रहा है। व्यापारियों को लगता है कि जब कोरोना खत्म होगा, तभी बिजनेस पहले की तरह चरम पर पहुंचेगा।

क्या शादी विवाह कम होने से घटी है मांग?

बत्रा का कहना है कि पहले फरवरी में खूब शादी-ब्याह होते थे। उस दौरान मसाले भी खूब बिकते थे। अब 18 अप्रैल से पहले कोई साया ही नहीं है। कहीं कोई खाने-पीने का फंक्शन होता है, तो कम गेस्ट आ रहे हैं, जिसके चलते दावत कम हो रही है। बर्थ डे पार्टियां और भंडारे भी पहले की तरह नहीं हो रहे हैं। इस समय बहुत जगहों पर होली मंगल मिलन प्रोग्राम होते थे। उसके ऑर्डर फरवरी में आते हैं, जो अभी नहीं आ रहे हैं।

ओरिएंटल इंश्योरेंस या यूनाइटेड इंडिया के निजीकरण पर विचार कर सकती है सरकार

नयी दिल्ली। सरकार ओरिएंटल इंश्योरेंस या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण पर विचार कर सकती है, क्योंकि पूंजी झोंके जाने के बाद इनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। मामले से जुड़े लोगों ने इसकी जानकारी दी। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों की वित्तीय स्थिति और बेहतर करने के लिये चालू तिमाही में अतिरिक्त तीन हजार करोड़ रुपये डालने वाली है। सूत्रों का कहना है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस और चेन्नई स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस दोनों अपनी बेहतर वित्तीय स्थिति के कारण निजी क्षेत्र की दिलचस्पी पाने में सक्षम हो सकती हैं। सूत्रों ने कहा कि निजीकरण के लिये एक उपयुक्त कंपनी चुनने की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है और इसे तय करने में कुछ समय लगेगा। उन्होंने कहा कि सूचीबद्ध न्यू इंडिया एश्योरेंस को चुने जाने की संभावना को भी खारिज नहीं करते हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस में सरकार की 85.44 प्रतिशत हिस्सेदारी है। योजना के अनुसार, नीति आयोग निजीकरण के लिये सरकार को सिफारिश करेगा और वित्त मंत्रालय का निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) प्रस्ताव पर निर्णय लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में दो सार्वजनिक बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की थी।

मैग्मा Q4 में 5000 ट्रक ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, हाइवे हीरोज कार्यक्रम करता है शुरू

कोलकाता। मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड ने प्रमुख सीएसआर कार्यक्रम, मैग्मा हाईवे हीरोज को फिर से शुरू किया, कोविद महामारी के कारण पड़ाव के बाद, 15 फरवरी 2021 को फरीदाबाद और जमशेदपुर में शिविर आयोजित किए गए। फरवरी और मार्च के बीच, 30 से अधिक शिविर होंगे। आयोजित और लगभग 5000 ट्रक ड्राइवरों को हरियाणा, एनसीआर दिल्ली, झारखंड, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण मिलेगा। मैग्मा 2015 से कार्यक्रम चला रहा है और उसने पहले ही देश के 300 स्थानों पर 1.85 लाख से अधिक ट्रक ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा और ईंधन दक्षता प्रशिक्षण की पेशकश की है। कार्यक्रम को सीएसआर मंचों पर कई राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से मान्यता मिली है और मार्च 2020 में, इसने भारत में ट्रक ड्राइवरों के लिए सड़क सुरक्षा शिक्षण कार्यक्रम के रूप में लिमाका बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रवेश किया। मैग्मा हाईवे हीरोज का

उद्देश्य सड़क सुरक्षा जागरूकता और ट्रक चालकों के बीच वाहनों के लिए बेहतर माइलेज है। कार्यक्रम पेट्रोलियम संरक्षण और अनुसंधान संघ (पीसीआरए), पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है। प्रशिक्षण शिविर समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली निम्नलिखित चुनौतियों का समाधान करता है। ●सड़क सुरक्षा और कौशल की कमी ●वाहन रखरखाव और पर्यावरण प्रदूषण ●कम आय, प्रेरणा और आकांक्षा की कमी के लिए अग्रणी ●थकान और स्वास्थ्य खतरे ●अनुचित स्वच्छता और चिकित्सा देखभाल

कार्यक्रम की बहाली पर बोलते हुए, श्री कौशिक सिन्हा, प्रमुख - सीएसआर, कॉर्प कॉम। मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड की कॉर्प और कॉर्प सर्विसेज ने कहा, 'हम फिर से शिविरों को फिर से शुरू कर खुश हैं। हाइवे हीरोज कैंपों ने हमारे आर्थिक विकास के उत्प्रेरक, ट्रक ड्राइवर्स के जीवन को इतना स्थायी अंतर दिया है। हमारी योजना 31 मार्च 2021 से पहले 5000 ट्रक ड्राइवरों को प्रशिक्षण प्रदान करने की है।' उसने जोड़ा।

News यू केन USE

रसायन, पेटोरसायन क्षेत्र 5 हजार अरब की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता है और ये सरकार के पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने मंगलवार को यह बात कही। रसायन और उर्वरक मंत्री ने यहां पेट्रोकेमिकल और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए 10 वें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। गौड़ा ने एक ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल्द से जल्द पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लक्ष्य को हासिल करने में रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र एक अग्रणी क्षेत्र के रूप में उभर सकते हैं। उन्होंने कहा, ''भारत में वैश्विक पेट्रोकेमिकल हब बनने की संभावना है और उच्च जीडीपी वृद्धि, कुशल जनशक्ति की उपस्थिति, बड़े घरेलू बाजार जैसे पहलु, इस क्षेत्र में निवेश के लिए भारत एक आकर्षक मंच बनाता है।'' राष्ट्रीय पुरस्कारों के वर्तमान संस्करण में, 273 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें से चार को विजेता और नौ को उपविजेता चुना गया।

इथोपिया ने भारतीय निवेशकों को दिया निवेश का निमंत्रण

कोलकाता। एजेंसी

इथोपिया ने मंगलवार को भारतीय निवेशकों को देश के प्राथमिक क्षेत्रों में निवेश का आह्वान किया और उम्मीद जतायी कि आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ेगा। इथोपिया की राजदूत तिजीता मुलुगेता ने कपड़ा और परिधान, चमड़ा और चमड़े के उत्पाद, कृषि प्रसंस्करण, पर्यटन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी था खनन एवं ऊर्जा को अपने देश के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र बताया। उन्होंने मर्चेन्ट चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत और इथोपिया के बीच व्यापार के हाल के वर्षों में 1.27 अरब डॉलर रहा। इथोपिया सरकार ने भारत के निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिये प्रोत्साहित करने को लेकर कई कदम उठाये हैं। उद्योग मंडल के अध्यक्ष आकाश शाह ने कहा कि इथोपिया 2025 तक अफ्रीका में मध्यम आय वाला देश और प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनने को पूरी तरह से तैयार है।

कोचीन शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिये 10,000 करोड़ रुपये के अनुबंध के लिये सबसे कम की बोली लगायी

नयी दिल्ली। कोचीन शिपयार्ड ने मंगलवार को कहा कि वह भारतीय नौसेना के 10,000 करोड़ रुपये के अनुबंध में सबसे कम की बोली लगाने वाली बोलीदाता रही है। यह अनुबंध अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाज बनाने के लिये है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग में प्रमुख कंपनी के रूप में उभरी है जो भारत में बड़े से बड़े जहाजों का निर्माण और मरम्मत कर सकती है। कोचीन शिपयार्ड लि. (सीएसएल) ने बीएसई को दी सूचना में कहा, ''रक्षा मंत्रालय ने 23 फरवरी को हुई बैठक में सीएसएल को भारतीय नौसेना की निविदा में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में घोषित की है। यह निविदा अगली पीढ़ी के छह मिसाइल जहाज के निर्माण के लिये है।'' कंपनी ने कहा कि इसका अनुमानित आर्डर मूल्य करीब 10,000 करोड़ रुपये है। सीएसएल ने कहा कि अनुबंध की अंतिम घोषणा इस संदर्भ में जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने पर निर्भर है। इसके बारे में उपयुक्त समय पर जानकारी दी जाएगी।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए

अमेज़न इंडिया ने महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ साझेदारी की

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करते हुए, अमेज़ॅन इंडिया ने आज महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। 2020 में, अमेज़न इंडिया ने घोषणा की थी कि भारत में उसके डिलीवरी वाहनों के बेड़े में 2025 तक 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) शामिल हो जायेंगे। ये ईवी 2030 तक डिलीवरी बेड़े में 100,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की वैश्विक प्रतिबद्धता के अलावा हैं, जिसके लिए अमेज़न ने क्लाइमेट प्लेज में हस्ताक्षर किये हैं। महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ अमेज़न की यह साझेदारी अपने पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ई-मोबिलिटी उद्योग में भारत की प्रगति की दिशा में अमेज़न का एक महत्वपूर्ण कदम है।

महिंद्रा ट्रिओ ज़ोर वाहनों को अब तक सात शहरों में तैनात किया गया है, जिनमें बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर और लखनऊ शामिल हैं, जहां अमेज़न इंडिया के डिलीवरी सर्विस पार्टनर्स का नेटवर्क है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय ई-मोबिलिटी उद्योग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति के कारण एडवान्ड टेक्नोलॉजी, और बेहतर मोटर और बैटरी कम्पोजनेंट्स उपलब्धट हुए हैं।

श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, भारत सरकार ने कहा कि 'जलवायु परिवर्तन को रोकने की कार्रवाई में स्वच्छ ऊर्जा द्वारा संचालित स्वच्छ मोबिलिटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। अमेज़न इंडिया और महिंद्रा इलेक्ट्रिक के बीच साझेदारी स्वागत योग्य कदम है, जो ई-मोबिलिटी उद्योग में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति की पुष्टि करता है, और हमारे पर्यावरण के सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऑटो निर्माताओं और ई-कॉमर्स कंपनियों की भूमिका की पहचान स्थापित करता है।

अखिल सक्सेना, वीपी, कस्टमर फुलफिलमेंट ऑपरेशंस, एपीएसी, एमईएनए एवं एलएटीएएम, अमेज़न ने कहा कि 'हम अपने ऑपरेशंस के पर्यावरणीय प्रभाव को कम से कम करने के लिएएक सप्लाई चेन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 2025 तक हमारे इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े में 10,000 वाहन शामिल हो जायेंगे, जो उद्योग में एक सस्टेनेबिलिटी लीडर बनने की हमारी यात्रा मेंमहत्वपूर्ण पड़ाव है। हम 'मेड इन इंडिया' इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा बनाने के लिए कई ओईएम के साथ काम कर रहे हैं, जो कस्टमर्स के ऑर्डर की सस्टेनेबल और सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं, और महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ यह साझेदारी हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।'

NSE पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण ट्रेडिंग रूकी, लोगों ने ट्विटर पर की शिकायत

नई दिल्ली। वैश्विक बाजारों से कमजोर संकेत के बावजूद बंबई शेयर बाजार (Share Market) का सेंसेक्स बढ़त के साथ खुला। वहीं एनएसई (NSE) पर बुधवार को तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ट्रेडिंग में परेशानी देखा गया। जिसके बाद से खुदरा निवेशक इस बात को लेकर ट्विटर पर अपनी शिकायत कर रहे हैं, उनका कहना है कि तकनीकी दिक्कत की वजह से उन्हें लंबे समय से एक ही इंडेक्स प्राइस देखने को मिल रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनएसई ने फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट को 11:40 बजे बंद कर दिया। वहीं कैश मार्केट को 11:43 बजे बंद कर दिया गया। एनएसई ने कहा है कि मार्केट को दोबारा खोलने को लेकर जल्द ही नया अपडेट जारी किया जाएगा

शेयरों में खरीदारी के बल पर 200 अंक चढ़ा

वहीं बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक जैसे प्रमुख शेयरों में खरीदारी के बल पर 200 अंक चढ़ गया। बंबई शेयर बाजार (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स कारोबार के शुरुआती दौर में 207 अंक यानी 0.42 प्रतिशत बढ़कर 49,958.41 अंक पर पहुंच गया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 69.35 अंक यानी 0.47 प्रतिशत बढ़कर 14,777.15 अंक पर पहुंच गया।

इन शेयरों में आई गिरावट

सेंसेक्स में शामिल शेयरों में एक्सिस बैंक करीब दो प्रतिशत की तेजी के साथ सबसे ज्यादा लाभ में रहा। इसके साथ ही बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी और अल्ट्रा टेक सीमेंट के शेयरों में भी लाभ दर्ज किया गया। इसके विपरीत टीसीएस, पावर ग्रिड, इन्फोसिस, हिन्दुस्तान यूनिलीवर और टेक महिन्द्रा के शेयरों में गिरावट का रुख रहा। बीएसई सेंसेक्स पिछले सत्र में 7.09 अंक यानी 0.01 प्रतिशत बढ़कर 49,751.41 अंक और निफ्टी 32.10 अंक यानी 0.22 अंक बढ़कर 14,707.80 अंक पर बंद हुआ था।

दूरसंचार विभाग ने कनॉट प्लेस में 48 गैरकानूनी मोबाइल सिग्नल बूस्टर हटाए

नयी दिल्ली। एजेंसी

दूरसंचार विभाग के वायरलेस निगरानी प्रकोष्ठ ने राष्ट्रीय राजधानी के कनॉट प्लेस में 48 मोबाइल सिग्नल बूस्टर को हटाया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि वायरलेस निगरानी संगठन दिल्ली के अन्य हिस्सों में भी इस गैरकानूनी उपकरण के खिलाफ अभियान चला रहा है और लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग स्टेशन के इंजीनियर-इन-चार्ज देवेंद्र कुमार राय ने कहा, ''हमने कनॉट प्लेस में 48 मोबाइल सिग्नल बूस्टर हटाए हैं। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि ये उपकरण गैरकानूनी है। जब हम उन्हें इसकी जानकारी देते हैं, तो वे सहयोग करते हैं और इन्हें हटा देते हैं।'' गैर- कानूनी मोबाइल सिग्नल रिपीटर एक बड़ी परेशानी की वजह बने हुए हैं। इनकी वजह से उपभोक्ताओं को कॉल ड्रॉप और कम डेटा स्पीड की दिक्कतों से जूझना पड़ता है। ये गैर- कानूनी रिपीटर मोबाइल सिग्नल को तेज करने के लिए व्यक्तिगत लोगों द्वारा घरों में या प्रतिष्ठानों द्वारा कार्यालयों में लगाए जाते हैं। राय ने कहा कि बूस्टर को हटाए जाने के बाद मोबाइल सिग्नल में सुधार होता है। दूरसंचार विभाग की टीम मोबाइल सिग्नल बूस्टर के खिलाफ दक्षिण दिल्ली जिले में छापेमारी कर रही है। दूरसंचार कंपनियां विभाग के समक्ष लगातार गैरकानूनी बूस्टर का मुद्दा उठाती हैं, क्योंकि इससे उनकी सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है। पिछले डेढ़ साल के दौरान दूरसंचार विभाग ऐसे 500 गैरकानूनी उपकरणों को हटा चुका है।

फियो ने आईजीएसटी से जुड़ी समस्याओं के समाधान की वित्त मंत्रालय की पहल का स्वागत किया

नयी दिल्ली।आईपीटी नेटवर्क

निर्यातकों की आईजीएसटी रिफंड से जुड़ी समस्या के निदान की दिशा में वित्त मंत्रालय की पहल किये का निर्यातक संघों के महासंघ फियो ने सराहना की है। संगठन ने कहा है कि इससे निर्यातकों का फंसा रिफंड जल्द मिलने में मदद मिलेगी। फियो के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ ने निर्यातकों की एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) से जुड़ी रिफंड की समस्या के निदान के लिये केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा एसबी005 और जीएसटीआर-3बी की गलतियों को सुधारने की पहल का स्वागत किया है। फियो की जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीबीआईसी ने आंकड़ों के मिलान की समस्या के निदान की पहल की है जिसके तहत एसबी005 से जुड़े .31 दिसंबर 2020 तक के सभी शिपिंग बिलों में सुधार किया जायेगा। वहीं, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के मिलान के मामले में 31 मार्च 2021 तक के आंकड़ों को सुधारा जायेगा। फियो प्रमुख ने कहा कि वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर उठाये गये कदम वास्तव में निर्यातक समुदाय के लिये काफी उत्साहवर्धक रहे हैं। उन्होंने सीबीआईसी द्वारा कोविड-19 के दौरान निर्यात माल की क्लीयरेंस जल्द करने और दूसरी सुविधाओं के लिये उठाये गये कदमों की भी सराहना की।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।